रीयल्टी कंपनियां चाहती हैं, अब ऋण पर ब्याज दर घटाएं बैंक

नई दिल्ली, (भाषा)। रिजर्व बैंक को अब बैंकों पर ब्याज दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने के लिए दबाव बनाना चाहिए। रीयल्टी क्षेत्र की कंपनियों और सलाहकारों ने आज मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर 6.25 प्रतिशत करने का स्वागत करते हुए कहा कि अब बैंकों को आवास रिण पर ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए जिससे आवास क्षेत्र की मांग बढ़ाई जा सके। क्रेडाई के अध्यक्ष गेतांबर आनंद ने पीटीआई भाषा से कहा, "हम दरों में कटौती का स्वागत करते है। लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब बैंक इसका लाभ आवास रिण लेने वाले ग्राहकों तथा अन्य खुदरा ग्राहकों को दें। ऐसा हो नहीं रहा है। यह अनुचित है। रिजर्व बैंक को बैंकों पर दरों में कटौती के लिए दबाव बनाना चाहिए।" देश की प्रमुख रीयल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव तलवार ने कहा, "यह रिजर्व बैंक द्वारा काफी अच्छी घोषणा है। नए गवर्नर और मौद्रिक नीति समिति ने एक प्रगतिशील फैसला लिया है।" तलवार नारेडको के चेयरमैन भी है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में आगे वृद्धि से आवास क्षेत्र की मांग पर सकारात्मक असर पड़ेगा। रीयल एस्टेट विशेषज्ञ तथा लोट्स ग्रीन्स के समूह निदेशक तपन सगल ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती रीयल एस्टेट क्षेत्र के लिए अच्छी है। हम उम्मीद करते है कि बैंक इसका लाभ अंतिम उपभोक्ता को देंगे। यह कटौती ऐसे समय की गई है जबकि रीयल एस्टेट कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इससे ग्राहक खरीद के बारे में फैसला कर सकेंगे। अल्फाकार्प के मुख्य कार्यकारी आशिष सरीन ने कहा कि रिजर्व बैंक के इस कदम से बैंकों के धन की लागत कम होगी और इस लिए बैंकों को चाहिए कि वे अपनी आधार दरें घटा कर इसका फायदा ग्राहक रिणवालों को दें। उन्होंने उम्मीद जताई की यह निर्णय 'रीयल एस्टेट क्षेत्र में उत्साह जगाने वाला' हो सकता है। नारेडको के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि इस कटौती से बाजार की धारणा सुधरेगी और मकानों की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी। जेएलएल के चेयरमैन एवं कंट्री प्रमुख अनुज पुरी ने कहा कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। त्योहारी सीजन से पहले इसकी जरूरत थी। सीएचडी डेवलपर्स के प्रबंध निदेशक गौरव मित्तल ने कहा कि बैंकों को इस कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देना चाहिए और मॉर्गेज दरों में कमी करनी चाहिए, जिससे घर के खरीदारों के लिए आवास रिण सस्ता हो सके। एसोटेक रीयल्टी के प्रबंध निदेशक नीरज गुलाटी ने कहा, "केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में चौथाई फीसद की कटौती से घरेलू आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, अभी यह कटौती अधिक नहीं लगती है, लेकिन यदि ब्याज दरों में निरंतर कटौती होती है और बैंक इसे ग्राहकों को देते है तो समय के साथ इसका आवास रिण पर व्यापक प्रभाव दिखाई देगा। नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजाल ने कहा, "हम उम्मीद करते है कि बैंक इसी अनुपात में लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान करेंगे।" सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा ने कहा कि इससे प्रापर्टी बाजार में सुस्ती दूर हो सकेगी। प्रॉपइक्विटी के संस्थापक समीर जसुजा ने कहा कि यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है क्योंकि ज्यादातर मकानों की बिक्री त्योहारी सीजन में होती है।